

75वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में
माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया जी का अभिभाषण

दिनांक : 26 जनवरी 2024, शुक्रवार	समय : 9.00 AM	स्थान : खानापाड़ा, गुवाहाटी
----------------------------------	---------------	-----------------------------

मेरे प्यारे असम वासियों,

आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। आज का दिन, हम सभी देशवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन् 1950 में, आज ही के दिन, भारतीय संविधान को लागू किया गया और भारत एक संप्रभुता-संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर, मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। साथ ही, मैं संविधान के निर्माताओं एवं उन दूरदर्शी नेताओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र की नींव रखी।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम “विकसित भारत” और “भारत-लोकतंत्र की मातृका” है।

मेरे प्यारे असम वासियों,

भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र भारत की आत्मा है। वह आम भारतीयों की साँसों और संस्कारों में रचा-बसा है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अवधारणाओं का विकास सहयोग, समन्वय एवं सह-अस्तित्व पर आधारित प्राचीन एवं सनातन सांस्कृतिक विचार-प्रवाह एवं जीवन-दर्शन से हुआ है।

भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी और व्यापक हैं कि यूरोप-अमेरिका समेत संपूर्ण विश्व इससे प्रेरणा ग्रहण करता है। अपनी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। हमें गर्व है कि हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा और सक्रिय लोकतांत्रिक देश है। भारत की उभरती शक्ति को दुनिया उम्मीदों से देख रही है। देश आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सारी विविधताओं पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है।

हमारा लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतांत्रिक राष्ट्र भारत मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक तौर पर भारत पांचवें स्थान पर है और आने वाले 5-6 वर्षों में अमेरिका, चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है।

राष्ट्र आज आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। भारत में कई क्षेत्रों में असाधारण प्रगति हुई है। स्वच्छ पेयजल, ऊर्जा, रोजगार, अच्छी सड़कें और रेल पथ के विस्तार जैसे मोर्चों पर हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान, सामरिक अनुसंधान, अत्याधुनिक सैनिक उपकरणों, मिसाइलों, तेजस विमानों, सैनिक साजो सामान, कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक खोजों, संचार एवं तकनीक, विदेश व्यापार, परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु शक्ति के क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है।

हमारी युवा पीढ़ी की अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन व दिशा दिखाकर उनकी क्षमताओं का समुचित दोहन करने का प्रयास निरंतर जारी है। सेवा क्षेत्र में हमारे युवा नई सोच एवं उच्च शिक्षा से बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं।

आज भारत के सामने नित नये अवसर बन रहे हैं, भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। हम 2047 तक "विकसित भारत" के संकल्प को भी पूरा करने में सक्षम होंगे। हमें विकास के साथ-साथ अपनी विरासत को सहेजना है। अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपना है। इसी सोच के साथ देश निरंतर आगे बढ़ रहा है।

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे असम से तीन विशिष्ठ लोगों को "पद्मश्री" से सम्मानित किया गया है। **श्रीमती पार्वती बरुवा** को समाजसेवा के क्षेत्र में, **श्री सर्वेश्वर बसुमतारी** को कृषि के क्षेत्र में और **श्री द्रोणा भुइयां** को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए श्रीमती पार्वती बरुवा, श्री सर्वेश्वर बसुमतारी, श्री द्रोणा भुइयां को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मेरे प्यारे असम वासियों,

यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे असम के विकास पथ को उजागर करने वाली प्रगति और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में उठाए गए परिवर्तनकारी कदम लोगों के कल्याण और भलाई के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है।

इस शुभ अवसर पर, मैं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभागों द्वारा हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियों को आपके साथ साझा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।

1. शांति

(क) शांति विकास और समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम असम में सर्वांगीण विकास देख रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि आज राज्य में शांति कायम है। पिछले वर्ष शांति समझौते के संदर्भ में हमें दो महत्वपूर्ण सफलता मिली। भारत सरकार की सक्रियता के चलते 29 दिसंबर, 2023 को अल्फा के साथ ऐतिहासिक समझौते के साथ शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई, जो दशकों से चले आ रहे टकराव के समापन का प्रतीक है। इससे पहले 27 अप्रैल, 2023 को दिमासा समझौता पर हस्ताक्षर

हुए, जो दिमासा लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। यह समझौता स्थानीय समुदायों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित है।

(ख) कई दशकों से असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मेघालय अपने गठन के बाद लंबे समय से सीमा विवादों से जूझ रहे थे। मेरी सरकार की मुख्य चिंता सीमा विवादों को हल करना है। इस प्रयास में 20 अप्रैल 2023 को असम-अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद सुलझा लिया गया। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के द्वारा दावा किए गए 123 गांवों में से 71 गांवों पर मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया है। मिजोरम ने भी असम के साथ अपने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत पर बल दिया है। इस संबंध में क्षेत्रीय समितियों के गठन पर चर्चा चल रही है।

(ग) हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास को सर्वोपरि रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने मौजूदा बीओपी को बेहतर बनाने और मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस दिशा में बीओपी प्रबंधन समितियों को वित्त पोषित किया गया है और अंतर-राज्य सीमा के साथ रणनीतिक स्थानों पर 50 नए बीओपी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

2. अपराध पर नियंत्रण

(क) सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है, जिसके लिए कानून-व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखना आवश्यक है। मेरी सरकार सामाजिक व्यवस्था को बाधित करने वाले सामाजिक मुद्दों, विशेष रूप से बाल विवाह और ड्रग्स के प्रचलन को खत्म करने को प्राथमिकता देती है। पिछले साल बाल विवाह के मामले में 8,800 आरोपियों के खिलाफ 5,347 मामले

दर्ज किए गए और 4,407 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। अब हमारा लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह को पूर्ण से समाप्त करना है। इसके लिए बाल विवाह निषेध अधिकारियों को तैनात किया गया है। हमारे विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, सोने की तस्करी और वन्यजीवों की तस्करी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो सामाजिक कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

(ख) असम सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रही है। असम पुलिस की सतर्कता और भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा सक्रिय रूप से भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों में लगी हुई है।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान रखते हुए असम पुलिस विघटनकारी तत्वों से सख्ती से निपट रही है और पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ पीएफआई और सीएफआई नेताओं को गिरफ्तार करने के अलावा 11 अंसारुल्ला बांग्ला टीम (एबीटी) को नष्ट करने में सफल रही है।

3. बुनियादी ढांचा

(क) शांति कायम होने के साथ राज्य अब ढांचागत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को हाई स्पीड रोड कॉरिडोर में सुधारने और उन्नत करने के लिए एक प्रमुख योजना “असम माला” लागू की गई है। 5 प्रमुख सड़कों का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इस परियोजना में डिब्रॉंग, सुबनसिरी और पगलादिया नदियों पर प्रमुख पुल का निर्माण शामिल हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित असम रेजिलिएंट रूरल ब्रिज प्रोजेक्ट में 1000 से अधिक पुलों के निर्माण, चौड़ीकरण और उन्नतिकरण का काम शुरू किया गया है। जिले में आपदा प्रतिरोधी सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए दिमा हसाओ जिले में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक नई परियोजना शुरू की गई है। गुवाहाटी शहर के अंतर्गत मालीगांव क्षेत्र के ए टी रोड में और आर जी बरुवा रोड में दो एलिवेटेड सड़कें पूरी हो चुकी हैं।

4. शहरी विकास

(क) माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से जोर दिया है कि "नए शहरों का विकास और मौजूदा शहरों में सेवाओं का आधुनिकीकरण शहरी विकास के दो मुख्य पहलू हैं"। माननीय

प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप हमारी सरकार नए शहर के विकास और मौजूदा शहरों के आधुनिकीकरण पर जोर देने के साथ शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। गुवाहाटी में हम स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। 100 सीएनजी बसें और 200 एसी ईवी बसें खरीदी गई हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। हमारा लक्ष्य 2025 तक गुवाहाटी को 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले पहले शहरों में से एक बनाना है।

(ख) ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहरी बाढ़ जोखिम के प्रबंधन के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दृष्टिकोण है, को बढ़ाने के लिए शहरी हरित आवरण और प्राकृतिक जल प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं। इसलिए गुवाहाटी में कई नए पार्क विकसित किए गए हैं। इस संदर्भ में फैंसी बाजार में 'बॉटैनिकल गार्डन' की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य के विभिन्न जिलों जैसे गोलाघाट, तिनसुकिया, तेजपुर आदि में भी कई पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा शिलसाको के जैसे कई आद्रभूमि क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्द्ध हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

5. प्रशासनिक सुधार

(क) हमारी सरकार ऋग्वेद में प्रतिपादित “बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय” के महान सूत्र के तहत काम कर रही है। इस सिद्धांत को अपनाने, लोगों की खुशी, उनके कल्याण और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार शुरू किए गए हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ 78 उप-जिलों का निर्माण है। नव स्थापित उप-जिलों में बीटीआर जिले और छठी अनुसूची जिले शामिल नहीं हैं।

(ख) हमारे सुधार उपायों की आधारशिला साप्ताहिक कैबिनेट बैठकें हैं, जो अब तक 114 कैबिनेट बैठकों में 1542 उल्लेखनीय निर्णयों को मंजूरी देने में सहायक रही हैं। इससे कुशल और जवाबदेह शासन सुनिश्चित हुआ है। परंपरा से हटकर पंद्रह कैबिनेट बैठकें राजधानी के बाहर आयोजित की गईं, जिससे लोगों के साथ सीधे संबंध को बढ़ावा मिला है।

(ग) जिला आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ नियमित सम्मेलन भविष्य के विकास के लिए अधिकारियों के विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य

करते हैं। इन बैठकों के माध्यम से हमारा लक्ष्य असम को व्यापक विकास और सुशासन में एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करना है।

(घ) सरकारी सेवाओं की त्वरित डिलीवरी को बढ़ाने के लिए हमने “सेवासेतु पोर्टल” पेश किया है, जो “असम राइट टू पब्लिक सर्विस” (एआरटीपीएस) पोर्टल की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें विभिन्न विभागों और स्वायत्त परिषदों की 541 महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। 22 जनवरी, 2024 तक पोर्टल के द्वारा 1,11,14,240 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 84% की सरहनीय दर से 93,81,221 आवेदनों का निपटान हुआ है। पेंशनभोगियों की चिंताओं को संबोधित करते हुए “कृतज्ञता 2.0” पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें वर्तमान में 59 विभाग पंजीकृत हैं। इस पोर्टल के तहत 20,484 पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं। 19,697 ऑनलाइन पेंशन भुगतान आदेश 96% निकासी दर के साथ जारी किए गए हैं। असम सरकार न केवल सेवानिवृत्ति और वीआरएस पेंशन को ऑनलाइन संसाधित करके, बल्कि पारिवारिक पेंशन, संचार, अमान्य अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पेंशन में संशोधन सहित अन्य पेंशन श्रेणियों में विस्तार सेवाओं

के माध्यम से अपने कर्मचारियों और पेंशन की सेवा कर रही है ताकि डिजिटल असम सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचा सके।

(ड) परिवहन विभाग आवेदक को डीटीओ कार्यालयों का दौरा किए बिना 50 संपर्क रहित और फेसलेस सेवाएं प्रदान कर रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किए जाते हैं जिन्हें डिजिटल रूप से संग्रहित किया जा सकता है।

(च) ईओडीबी के तहत “सिंगल विंडो क्लियरेंस” पोर्टल का विस्तार 20 विभागों और 38 सरकारी संगठनों से 228 सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। आज तक प्राप्त लगभग 18 लाख आवेदनों में से 99% ऑनलाइन आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।

6. आर्थिक विकास

(क) शांति की स्थापना, सामाजिक व्यवस्था के सामान्यीकरण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक सुधारों और सुशासन से प्रेरणा के साथ, राज्य की

अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मेरी सरकार की यह उल्लेखनीय उपलब्धि विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में परिलक्षित हुई है, जिससे वित्त वर्ष 2022-23 में 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजटीय व्यय हुआ और अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ रुपये के जीएसडीपी को पार कर गई। हमारी सरकार पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से हरित बजट और अनुकूलनीय बजट शुरू करने पर भी जोर दे रही है। इस वर्ष हमारा पूंजीगत व्यय अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में लगभग 11000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश दर्ज किया जा चुका है। चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) का आवंटन 3100 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस आवंटन में से नाबार्ड ने अब तक कुल 475 परियोजनाओं के लिए 2788.11 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

(ख) हम बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत हमारा समर्थन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, जिसमें आज असम के मुख्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 35000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं। पूंजी निवेश

योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत राज्य का निधि आवंटन 2020-21 में 430 करोड़ से बढ़कर पिछले वर्ष 4300 करोड़ हो गया है। इस वर्ष हमें पूंजीगत मद के तहत अपनी योजनाओं को समर्थन देने के लिए 3000 करोड़ रुपये से अधिक पहले ही मिल चुके हैं। एनआईडीए के तहत नाबार्ड के सहयोग से असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एजेंसी (एआईएफए) ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्रों को कवर करते हुए 6000 करोड़ रुपये की पूंजी परियोजनाएं शुरू की हैं।

7. औद्योगिक विकास और निवेश

(क) उद्योगों के विकास और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए एक नई कस्टोमाइज़्ड औद्योगिक नीति 100 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश वाले निवेशकों के लिए डिज़ाइन की गई है। नीति के तहत 10,450 नौकरी के अवसरों के साथ कुल 11,315.14 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 14 प्रमुख निवेशकों के साथ समझौता ज़ापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इथेनॉल राज्य में एक संभावित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 1,154 करोड़ रुपये के निवेश के लिए तेल विनिर्माण कंपनियों द्वारा 7

निजी परियोजनाओं को विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के रूप में चुना गया है, जिससे संभावित रूप से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी।

8. कृषि क्षेत्र

(क) कृषक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने “धान खरीद कार्यक्रम” के तहत धान किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू किया है। चालू खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) में 169 धान खरीद केंद्रों (पीपीसी) के माध्यम से 7.04 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य है। सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए सरसों की खरीद भी शुरू की है, जिससे रबी 2022-23 के दौरान मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत 3273.30 मीट्रिक टन की खरीद से 1128 किसानों को लाभ हुआ है।

(ख) कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, हमारी सरकार ने कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएम) की स्थापना की है। 95% सरकारी सब्सिडी द्वारा समर्थित इस परिवर्तनकारी पहल ने कृषि पद्धतियों में क्रांति लाते हुए लक्षित 80 में से 78 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की सफलतापूर्वक स्थापना की है।

(ग) जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रति असम के अंतर्निहित झुकाव को देखते हुए हमारी सरकार सक्रिय रूप से पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है। कुल 10,244 किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा संचालित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया है। ये प्रयास न केवल टिकाऊ और जैविक कृषि पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों के महत्व पर जोर देते हुए वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं के अनुरूप भी हैं।

(घ) कृषि विभाग के प्रयासों से जनवरी से अगस्त 2023 तक असम का कृषि निर्यात 1,185 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पारंपरिक उत्पादों से परे अन्य उत्पादों में वृद्धि को दर्शाता है।

(ङ) प्रचुर जल संसाधनों से समृद्ध हमारा राज्य जल निकायों के विकास और जलीय कृषि के विस्तार के माध्यम से आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं रखता है। वर्तमान में असम अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्य के रूप में चौथे स्थान पर है और देश भर में समग्र मछली उत्पादन में 12वें स्थान पर है। 4000 हेक्टेयर राज्य फिश बील मत्स्य पालन के सतत विकास,

प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए असम के मत्स्य विभाग ने “स्विफ्ट” नामक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) के कार्यान्वयन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र को और बढ़ाना है।

(च) पशु चिकित्सा क्षेत्र में हमारी सरकार विशेष रूप से सुअर पालन पर जोर दे रही है, सुअर पालन की क्षमता को पहचान रही है और चालू वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र में सुअर पालन के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। इसके अतिरिक्त राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 4 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए 181 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो पशुपालकों को उनके पशुओं के स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए घर-घर सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

(छ) उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के वित्त पोषण समर्थन से डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पटाचारकुची, बजाली में 10,000 लीटर प्रतिदिन का दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

9. सार्वजनिक स्वास्थ्य

(क) स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में हमारे राज्य ने एक मील का पत्थर हासिल किया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कामरूप के चांगसारी में उत्तर पूर्व भारत में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोकराझार, नलबाड़ी और नगांव में स्थापित तीन नए मेडिकल कॉलेजों को भी समर्पित किया है। तिनसुकिया में 13वें मेडिकल कॉलेज का निर्माण फिलहाल हो रहा है।

(ख) स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए चराईदेव, बांगईगांव, बिश्वनाथ और कामरूप (मेट्रो) में चार नए मेडिकल कॉलेज निर्माण के उच्च चरण में हैं। गोलाघाट, तामुलपुर, धेमाजी और मोरीगांव मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रगति स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, गोवालपारा, करीमगंज और शिवसागर में तीन और मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) कुल परियोजना लागत 2510 करोड़ रुपये है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित "असिस्ट" (ASSIST) परियोजना के तहत, 2.5 वर्षों से परिचालन लागत सहित 10 नए जिला अस्पतालों का

निर्माण चल रहा है। इस परियोजना में 25 मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि भी शामिल है।

(घ) मेरी सरकार का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम “आयुष्मान असम - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना” (एए-एमएमजेएवाई) है। 2 अक्टूबर, 2023 को शुरू की गई यह योजना अतिरिक्त 28 लाख परिवारों को कवर करती है, जो कैशलेस उपचार के लिए पात्र बन गए हैं। इस प्रकार, “आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” (एबी-पीएमजेएवाई) और “आयुष्मान असम - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना” (एए-एमएमजेएवाई) ने लगभग 1.98 करोड़ लाभार्थियों वाले 58 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

(ङ) राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन आईटी पोर्टल के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए “आयुष्मान असम - मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना” (एए-एमएमएलएसएवाई) भी शुरू की। इससे इलाज करा रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सहज और निर्बाध प्रतिपूर्ति प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

10. शिक्षा

(क) शिक्षा हमारी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, और राज्य में इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास समर्पित किए गए हैं। “गुणोत्सव” का पांचवां दौर वर्तमान में चल रहा है, जिसमें 43,498 सरकारी, प्रांतीयकृत, चाय बागान मॉडल स्कूल, केजीबीवी, आवासीय विद्यालय, आदर्श विद्यालय और चाय बागान प्रबंधन स्कूल शामिल हैं। इस कार्यक्रम में 39,63,542 छात्र (कक्षा I से IX) और 18,098 बाहरी मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं, जो शैक्षिक उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

(ख) सात सरकारी मॉडल कॉलेजों ने परिचालन शुरू कर दिया है, और 126 शिक्षण पद सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा प्रांतीयकृत कॉलेजों में 133 शिक्षण (सहायक प्रोफेसर) और 557 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।

(ग) एनआईडीए के तहत बोंगाईगांव, बेहाली और सुआलकुची में और रूसा (RUSA) के तहत नलबाड़ी, नगांव, उदालगुड़ी में छह नए इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

एसओपीडी के तहत हाजो, माजुली, तिगखोंग में और सीएसएस के तहत दरंग, कार्बी-आंगलोंग, नगांव, धुबड़ी और दिमा हसाओ में अन्य आठ नए पॉलिटेक्निक भी चल रहे हैं, जो राज्य के आंतरिक हिस्सों में तकनीकी शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं।

(घ) ड्रॉपआउट दरों को कम करने और शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रेरित करने के लिए कक्षा 9 के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना, एचएसएलसी परीक्षाओं में उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए आनंदराम बरूवा नकद पुरस्कार और डॉ. बानीकांत काकती पुरस्कार के तहत स्कूटर वितरित करने जैसी पहल लागू की गई हैं। नौवीं कक्षा के कुल 3,69,454 छात्रों को साइकिलें मिलीं और एचएसएलसी की परीक्षा में 75 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 27,183 विद्यार्थियों को आनंदराम बरूवा नकद पुरस्कार के अंतर्गत प्रति 15,000 रुपये प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

(ङ) चाय जनजातियों और आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को छात्रवृत्ति जारी कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पाठ्यक्रमों के आधार पर न्यूनतम

3,000 रुपए से अधिकतम 35,000 रुपए तक के लिए कुल 65,078 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

11. सामाजिक सुरक्षा

(क) इस वर्ष हम अपने गणतंत्र के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। इस अवसर को वास्तव में महत्वपूर्ण बनाने के लिए, असम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार ने शांति सुदृढीकरण, आर्थिक समृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से एक मजबूत नींव रखी है। हमारा दृष्टिकोण अंतिम जन तक सुविधा पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दृष्टिकोण से प्रेरणा लेता है। सरकार महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

(ख) हमारे राज्य में महिलाओं के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार ने “अरुणोदय योजना” शुरू की। हाल ही में लॉन्च किए गए “अरुणोदय 2.0” का कवरेज न केवल

अंत्योदय महिलाओं तक है, बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन और दीन दयाल दिव्यांगजन पेंशन योजना और इंदिरा मिरी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजना के मौजूदा लाभार्थी भी शामिल हैं। वर्तमान में सरकार 25 लाख अरुणोदय परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 1250 रुपए प्रति माह सहायता प्रदान करती है।

(ग) हमारी सरकार ने अंतिम-जन तक वितरण को प्राथमिकता देते हुए असम माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना (एएमएफआईआरएस), 2021 की स्थापना की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में विभिन्न माइक्रोफाइनेंस ऋण संस्थानों से छोटे ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं को प्रोत्साहन और राहत प्रदान करना है। आज तक लगभग 12 लाख सूक्ष्म-उधारकर्ता इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, जिसका परिचय 2000 करोड़ रुपये से अधिक है।

(घ) हमारी सरकार ने चाय जनजातियों और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासी समुदाय के लिए

ओबीसी कोटा के भीतर 3% आरक्षण आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने चाय जनजातियों और आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षित मेडिकल सीटें 27 से बढ़ाकर 30 कर दी हैं। यह राज्य सरकार का वंचितों को ऊपर उठाने के लिए लिये गए फैसले का एक सरहनीय उदाहरण है।

(ड) सभी आरक्षित श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, “मिशन भूमिपुत्र” नामक एक आवश्यक मिशन को अपनाया गया है। इस मिशन का उद्देश्य जाति प्रमाण पत्र आवेदनों को जारी करने और शीघ्र निपटान को सुव्यवस्थित करना है। “मिशन भूमिपुत्र” सभी जातियों के लिए एकीकृत ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से एसटी/एससी/ओबीसी आवेदकों को डिजिटल रूप से जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहता है। अपने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं या “मिशन भूमिपुत्र” के तहत जिला आयुक्त, उपमंडल अधिकारी और सर्कल अधिकारी कार्यालयों या सामान्य सेवा केंद्रों में स्थित सार्वजनिक सुविधा केंद्रों का उपयोग कर सकते हैं।

(च) 14 नवंबर, 2022 को लॉन्च किया गया “मिशन बसुंधरा 2.0” अगली पीढ़ी की भूमि-संबंधी सेवाओं की शुरुआत करता है। 31 दिसंबर, 2023 तक प्राप्त 13,39,605 आवेदनों में से 2,26,934 आवेदकों को 'सेटलमेंट प्रस्ताव' जारी किए जा चुके हैं। “मिशन बसुंधरा 2.0” के तहत छह सेवाओं के लिए एसटी, एससी, ओबीसी और एमओबीसी श्रेणी के आवेदकों से प्राप्त कुल 6,89,155 आवेदनों में से 1,90,387 आवेदकों को 'निपटान का प्रस्ताव' दिया गया।

12. पहचान का संरक्षण

(क) स्थानीय और जनजातीय आस्था और संस्कृति की सुरक्षा, प्रचार और संरक्षण के लिए हमारी प्रतिबद्धता में सरकार ने 18 मूल निवासी और जनजातीय आस्था और संस्कृति संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया है, साथ ही मूल निवासी और जनजातीय आस्था और संस्कृति को समर्पित 73 पूजा स्थलों का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त उदालगुड़ी जिले के बहिरबकुंडा में दुलाराई बाथौ गौथुम (अखिल बाथौ महासभा) और कालीचरण ब्रह्मा सेवाश्रम में एक सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए अनुदान सहायता आवंटित की गई।

(ख) इसके अतिरिक्त, 2 करोड़ रुपये कामरूप मेट्रो जिले के दुलाराई बाथौ गौथुम (अखिल बाथौ महासभा) को संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए सहायता अनुदान आवंटित किया गया और बहिराबकुंडबाट उदालगुरी जिले में कालीचरण ब्रह्म सेवाश्रम को 15 लाख रुपये आवंटित किए गए।

13. खेल, संस्कृति और विरासत

(क) खेल और युवा कल्याण विभाग सक्रिय रूप से खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहा है और जमीनी स्तर के मेगा खेल आयोजन "खेल महारण" के माध्यम से प्रतिभाओं की पहचान कर रहा है। प्रतियोगिता ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर से एलएसी स्तर और जिला स्तर तक फैली हुई है, जिसका समापन 28 जनवरी से 6 (छह) अलग-अलग स्थानों पर शुरू होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में होगा। इस आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो-खो शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, 27.26 लाख से अधिक खिलाड़ियों/एथलीटों ने जीपी स्तर पर भाग लिया है, जिसने खेल महारण को राज्य में सबसे बड़े जमीनी स्तर के खेल आयोजन के रूप में स्थापित किया है। विशेष रूप से अंडर -19 श्रेणी में लगभग 70,000 खिलाड़ियों और

एबोव (above) -19 श्रेणी में लगभग 40,000 खिलाड़ियों की पहचान जीपी स्तर पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी क्षमता के लिए की गई है।

(ख) खेलों को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए पहल की है। तीन अत्याधुनिक स्टेडियम वर्तमान में डिब्रूगढ़ जिले के खानिकर, लखीमपुर जिले के सबोती और कामरूप जिले के सुआलकुची में कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से गुवाहाटी और जोरहाट में दो उच्च-प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) असम सरकार द्वारा शुरू किए गए असम सांस्कृतिक महासंग्राम 2023-24 का उद्देश्य राज्य में छिपी प्रतिभाओं की खोज करना और व्यक्तियों को अपनी संगीत और नृत्य कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में 12 से 35 वर्ष तक के विभिन्न आयु समूहों को चार अलग-अलग गायन श्रेणियों में शामिल किया गया है: ज्योति

संगीत, बिष्णु राभा संगीत, भूपेन्द्र संगीत और रवीन्द्र संगीत। इसके अतिरिक्त दो समूह नृत्य श्रेणियों में बिहू नृत्य और जातीय नृत्य शामिल हैं। प्रतियोगिताओं के लिए 10 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और 3 लाख से थोड़ा अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे आयोजन देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी।

(घ) हमारी सरकार हमारे पूर्वजों से मिली समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हम देश से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता के लिए एकमात्र प्रस्ताव के रूप में चराइदेव मैदाम को नामित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली मैदाम पर एक मसौदा नामांकन डोजियर यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS) के एक विशेषज्ञ ने पहले ही चराइदेव मैदाम पुरातत्व स्थल का मूल्यांकन कर लिया है। 24 नवंबर, 2023 को पेरिस, फ्रांस में ICOMOS

मुख्यालय में एक विश्व धरोहर पैनल समर्पित बैठक हुई, जिसमें भारत सरकार और असम सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

(ड) 14 अप्रैल, 2023 को एक ही स्थान पर सबसे बड़े बिहू प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई। इस असाधारण उपलब्धि में राज्य भर से 11,369 बिहू कलाकारों ने इस मेगा इवेंट में भाग लिया। यह भव्य अवसर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से गौरवान्वित हुआ।

14. युवा नेतृत्व विकास

(क) राज्य सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियाँ प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के प्रति दृढ़ है। राज्य स्तरीय भर्ती आयोग (एसएलआरसी) ने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए पहले ही उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। वादे को पूरा करने की अपनी यात्रा में मेरी सरकार पहले ही सरकारी नौकरियों में 88,547 रिक्तियां भर चुकी है।

(ख) युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर असम

अभियान (सीएमएएए) का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 2 लाख पात्र लाभार्थियों को चुनना है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 में चयनित 1 लाख लाभार्थियों को 2 लाख रुपये (सामान्य श्रेणी) और 5 लाख रुपये (व्यावसायिक पाठ्यक्रम) की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। सीएमएएए के तहत 2.29 लाख आवेदकों ने पंजीकरण कराया है।

(ग) उद्यमिता और स्टार्टअप के माध्यम से राज्य के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, हमारी सरकार ने सिडबी के सहयोग से 200 करोड़ रुपये का असम वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य असम को स्टार्टअप हब बनाना है। इस पहल से 257 स्टार्टअप लाभान्वित हुए हैं, जिससे उन्हें कुल 74 करोड़ रुपये की बाहरी धनराशि प्राप्त हुई है और उन्होंने 33 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न किया है। इसके अतिरिक्त, “माई असम स्टार्ट-अप आईडी” (एमएसआई) कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त 272 स्टार्टअप्स को चार करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार रुपये का अनुदान दिया गया। असम स्टार्ट-अप फेस्ट का अगस्त 2023 में उद्घाटन किया गया।

(घ) सिडबी के समन्वय से 100 करोड़ रुपये के कॉर्पस समर्थन के साथ 5000 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो निर्माण के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों को असम क्रेडिट गारंटी योजना को 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी बनाया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण में भारी सुधार हुआ है, क्योंकि वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों में 16,000 करोड़ से अधिक का ऋण प्रदान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से लगभग 60% सुधार है।

(ड) राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) के तहत, रोजगार के अवसरों को बढ़ाते हुए, जिला रोजगार कार्यालयों में सात मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किए गए हैं। Naukri.com के साथ हमारी सरकार के MoU के कारण 4 जुलाई, 2023 को असम जॉब पोर्टल (job.assam.gov.in) का सफल लॉन्च हुआ, जिससे स्थानीय और बाहर नौकरी चाहने वालों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

15. पर्यावरण

(क) विकास की हमारी खोज में पर्यावरणीय स्थिरता एक प्राथमिकता बनी हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने

और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अभिनव अमृत वृक्ष योजना शुरू की। 17 सितंबर, 2023 को एक विशाल वृक्षारोपण अभियान में 53 व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य वृक्ष प्रजातियों के एक करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए। इस पहल ने जनभागीदारी का लाभ उठाते हुए एसएचजी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, वीडिपी सदस्यों, चाय बागानों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी विभागों को शामिल किया। अमृत वृक्ष आंदोलन, 2023 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए।

(ख) संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, 200 वर्ग किमी में फैले ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के दूसरे हिस्से को आधिकारिक तौर पर 25 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था। 28 मई से 1 जून, 2023 तक आयोजित एक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान ने संपूर्ण अतिक्रमित क्षेत्र को मुक्त करवा लिया। इससे क्षेत्र में हाथी, बाघ, गैंडा, जंगली भैंस और हॉग हिरण जैसी विभिन्न जंगली जानवरों की प्रजातियाँ वापस आ गई हैं। इसके अतिरिक्त, बुरहाचपोरी

वन्यजीव अभयारण्य और चिरांग रिजर्व वन में 1482 हेक्टेयर भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है।

(ग) असम नदी पुनर्जीवन गतिविधियों, उद्योगों आदि द्वारा अपशिष्ट उपचार के सख्त प्रवर्तन आदि सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रदूषित नदी खंडों की संख्या को चौवालीस (44) से घटाकर नौ (9) करने में सफलता प्राप्त हुई है।

16. बाढ़ एवं कटाव

(क) जल संसाधन विभाग ने 4512.525 किमी तटबंध का निर्माण, 1219 कटाव-रोधी और शहर संरक्षण कार्य, 119 प्रमुख स्लुइस, 545 छोटे स्लुइस, 899.829 किमी जल निकासी चैनल और 986.944 किमी मौजूदा बांध को ऊपर उठाकर और मजबूत कर राज्य के 31.05 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 16.50 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित भूमि की रक्षा की है।

17. केन्द्रीय फ्लैगशिप योजनाओं का कार्यान्वयन

(क) केंद्रीय प्रमुख योजनाओं ने राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत असम को 2023 में कुल 8,805.28 करोड़ रुपये का फंड मिला है, जिसमें केंद्रीय हिस्से से 7,924.75 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से से 880.52 करोड़ रुपये शामिल हैं। राज्य ने प्राप्त फंड के मुकाबले 9,138.44 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। पीएमएवाई-जी को पूरक करने के लिए हमारी सरकार ने 2023-24 में पीएमएवाई-जी के छूटे हुए लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए एक राज्य प्रमुख योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (एमएमएवाई-जी) भी शुरू की है।

(ग) किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत 487.38 करोड़ रुपये की 15वीं किस्त जारी की गई। इससे 12.16 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला। सरकार इस वर्ष के भीतर सभी पात्र किसानों को इस योजना में शामिल करना सुनिश्चित करेगी।

(घ) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, इस योजना की वर्ष 2018 से राज्य में शुरुआत से अब तक 10.00 लाख लाभार्थियों को कैशलेस

चिकित्सा उपचार प्रदान करने की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहा है। उनमें से 4 लाख से अधिक लाभार्थियों ने वर्ष 2023 में 588 करोड़ रुपये के कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है। एबी-पीएमजेवाई के तहत एनएफएसए के अधीन 30 लाख परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के कैशलेस चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ड) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर की दैनिक आपूर्ति के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है, असम ने 2019 में जेजेएम के लॉन्च पर 1.6% एफएचटीसी कवरेज के साथ शुरुआत की थी और 2023 के अंत तक लगभग 71.28% घरों को कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।

(च) असम में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के हिस्से के रूप में युवा छात्रों का एक कैडर “जल दूत” के रूप में तैनात किया गया है। ये जलदूत “जलशाला” नामक विशेष रूप से डिज़ाइन की गई कार्यशालाओं के माध्यम से सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किए गए हैं। वर्तमान में, 22,000 से अधिक

जल दूत हैं, और निकट भविष्य में लगभग 3 लाख जल दूतों को शामिल करने की योजना है।

अंत में, मैं असम में हमारी सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रगति और पहल को साझा करने के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जिसका उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देना और हमारे नागरिकों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में दूरदर्शी नीतियों से लेकर संपोषित पर्यावरणीय प्रथाओं और सांस्कृतिक संरक्षण तक, हमारे सामूहिक प्रयासों ने एक समृद्ध और समावेशी असम के लिए मार्ग तैयार किया है।

जैसा कि हम अपने गणतंत्र के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं, हम समाज के हर वर्ग के उत्थान, सभी के लिए प्रगति, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ हैं।

आइए, कृतज्ञता और समर्पण के साथ हम अपने प्यारे राज्य के लिए जिस उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते हैं, उसके लिए मिलकर काम करना जारी रखें।

जय हिन्द !